

वर्षिष/द बगि पकिचर: इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) और Living Will का अधिकार

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

कोमा जैसी स्थिति में पहुँचने पर या किसी असाध्य रोग की पीड़ा लंबे समय तक भोगने वाले किसी व्यक्ति को क्या स्वयं को जीवित रखने या इच्छामृत्यु चुनने का अधिकार दिया जा सकता है?

इस सवाल पर देश के सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च को ऐतिहासिक फैसला देते हुए **इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia)** की अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही इसके लिये कड़े दशा-नरिदेश भी जारी किये हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उस याचिका पर आया है जिसमें लाइलाज बीमारी से जूझ रहे ऐसे व्यक्ति के लिये इच्छामृत्यु की इजाजत देने की मांग की गई थी, जिसके स्वास्थ्य में सुधार होने की कोई संभावना नहीं रह गई है। सुप्रीम कोर्ट की पाँच सदस्यों वाली संवधान पीठ ने पछिले साल 12 अक्टूबर को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इस मामले में पाँच न्यायाधीशों ने चार अलग-अलग राय रखी, लेकिन सभी ने एकमत होकर **लविगि वलि** पर सहमत जताई। वर्षिष परिस्थितियों के तहत इच्छामृत्यु की मांग करने वाले लोगों को लिखित रूप में लविगि वलि देनी होगी। इस मामले में कानून बनने तक फैसले में प्रतपिदति दशा-नरिदेश प्रभावी रहेंगे।

क्या कहा अदालत ने?

शीर्ष अदालत की पाँच सदस्यों वाली संवधान पीठ (मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मशिरा, ए.के. सकिरी, ए.एम. खानवलिकर, डी.वाई. चंद्रचूड़ और अशोक भूषण) ने अपने फैसले में मनुष्यों को पूरी गरमि के साथ मृत्यु का वरण करने का अधिकार देने की बात कही।

ये दशा-नरिदेश जारी किये

- गरमिपूर्ण मृत्यु पीडारहति होनी चाहिये और कुछ ऐसी प्रकरिया होनी चाहिये जिसमें गरमिपूर्ण तरीके से मृत्यु हो सके। लविगि वलि कौन कर सकता है? इसकी प्रकरिया क्या होगी? इसके लिये दशा-नरिदेश जारी किये गए हैं, अर्थात लविगि वलि और इच्छामृत्यु के इस नए अधिकार का दुरुपयोग रोकने के लिये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधान किये हैं।
- असाध्य बीमारी से ग्रस्त मरीजों के मामले में ऐसे मरीज के नज़दीकी मतिर और संबंधी इस तरह अग्रमि नरिदेश दे सकते हैं और लविगि वलि का नषिपादन कर सकते हैं।
- ऐसे लोगों को इच्छामृत्यु की वसीयत (Living Will) करने की भी अनुमति दी गई है, जो मेडिकल कोमा में रहने या लाइलाज बीमारी से ग्रसति होने की वज़ह से इच्छामृत्यु चाहते हैं।
- लविगि वलि को लेकर ऐसे व्यक्ति की पूरी छानबीन होगी, जसि संपत्तिया वरिसत में लाभ होने वाला हो।
- इच्छामृत्यु पर आखिरी फैसला मेडिकल बोर्ड तय करेगा कि इलाज संभव है या नहीं और यह नरिणय लेने के लिये स्वतंत्र होगा कि मरीज से लाइफ सपोर्ट ससिस्टम हटाया जाना चाहिये या नहीं।
- यदि मेडिकल बोर्ड कहेगा कि इलाज संभव नहीं है तो लाइफ सपोर्ट ससिस्टम हटा सकते हैं।

कौन लिख सकता है लविगि वलि?

- ऐसा कोई भी वयस्क इच्छामृत्यु की वलि लिख सकता है, जो स्वस्थ और मानसिक रूप से स्थिर तथा संवाद करने की हालत में हो।
- उसे दस्तावेज़ को समझने और इसके परिणामों के बारे में जानकारी होनी चाहिये।
- लविगि वलि स्वैच्छिक होनी चाहिये तथा उसके पीछे कोई दबाव या मजबूरी नहीं होनी चाहिये।

- इस वलि में स्वीकृत के तत्त्व होने चाहिये तथा इसको लिखने के पीछे कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिये ।
- न्यायालय के हिसाब से वसीयतकर्त्ता को स्पष्ट करना चाहिये कि उसे असाध्य रोग होने की हालत में क्या उसका मेडिकल इलाज हटाया जाए और क्या वशिष इलाज न दिया जाए ।
- वसीयतकर्त्ता किसी भी समय अपनी वलि में लिखे वायदों से पीछे हट सकता है ।
- उसे यह भी बताना होगा कि वह बेहोश हो तो उसका कौन-सा नकिट संबंधी नरिणय लेगा ।

कार्रवाई

- वसीयतकर्त्ता यदि असाध्य रूप से बीमार हो जाए और उसे जीवन रक्षक उपकरणों पर रखा गया है तो इलाज करने वाला चकित्सक मजस्ट्रेट से वसीयत की वास्तविकता की जाँच करेगा और इसके अनुरूप ही कार्रवाई करेगा ।
- एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें कम-से-कम तीन 20 साल के अनुभव वाले जनरल मेडिसिनि, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, साइकियाट्री और कैंसर के वशिषज्ञ शामिल होंगे ।
- ये वशिषज्ञ मरीज़ के परजिनों की उपस्थिति में उसे देखेंगे और तय करेंगे कि उसके चल रहे इलाज हटाए जाएं या बंद किये जाएँ ।
- मेडिकल बोर्ड यदि यह तय करता है कि इलाज हटाना ठीक रहेगा तो इलाज करने वाला चकित्सक क्षेत्र के कलेक्टर को इसकी जानकारी देगा । कलेक्टर भी एक मेडिकल बोर्ड का गठन करेगा, जिसमें ज़िले के सीएमओ और तीन वशिषज्ञ चकित्सक शामिल होंगे ।
- ये बोर्ड के साथ अस्पताल जाएंगे और मरीज़ को देखेंगे । यदि ये पाते हैं कि अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की सलाह अमल करने लायक है तो लविगि वलि में लिखे नरिदेशों को लागू करने के लिये प्रमाणपत्र जारी करेंगे ।
- इससे पहले वे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजस्ट्रेट को सूचित करेंगे, जो मरीज़ से मल्लिगा और बोर्ड के फ़ैसले को लागू करने के लिये अधिकृत करेगा ।
- इसके लागू होने से पूर्व वसीयतकर्त्ता के पास इससे पीछे हटने का वकिल्प खुला रहेगा ।
- यदि मेडिकल बोर्ड मना कर देता है तो मरीज़ के परजिनों के पास उच्च न्यायालय जाने का वकिल्प है । ऐसी स्थिति में वशिष खंडपीठ का गठन कर मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा ।
- इसके बाद सरकारी वकीलों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय जल्द-से-जल्द फ़ैसला लेगा और यदि इसमें देरी होती है तो इसके कारणों का वसित्त ब्योरा देगा ।

सत्यापन

- यदि दो लविगि वलि लिखी गई हैं तो बाद में लिखी गई वलि ही मान्य होगी ।
- वलि पर वसीयतकर्त्ता के हस्ताक्षर के साथ दो गवाहों के हस्ताक्षर भी होने चाहिये ।
- इस वलि को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजस्ट्रेट से सत्यापित करवाना अनवार्य होगा ।
- मजस्ट्रेट एक कॉपी अपने पास रखेगा तथा एक अन्य कॉपी डिजिटल प्रारूप में रखी जाएगी ।
- मजस्ट्रेट द्वारा एक कॉपी जिला जज को भेजी जाएगी और वहाँ भी एक कॉपी डिजिटल प्रारूप में रखी जाएगी ।
- मजस्ट्रेट वसीयतकर्त्ता के परजिनों को सूचित करेगा और उन्हें वसीयत के बारे में बताएगा ।
- एक कॉपी नगरपालिका या पंचायत को दी जाएगी, जो एक उचित प्राधिकार को नामति करेंगे, जिसके पास दस्तावेज़ सुरक्षित रहेगा अर्थात् ये कस्टोडियन का काम करेंगे ।
- वलि की एक कॉपी वसीयतकर्त्ता के फ़ैमिली डॉक्टर को भी दी (यदि कोई है) जाएगी ।

- एनजीओ 'कॉमन कॉज़' ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखल कर कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जसि तरह नागरिकों को जीने का अधिकार दिया गया है, उसी तरह उन्हें मरने का भी अधिकार है।
- सुप्रीम कोर्ट ने असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को नषिक्रयि अवस्था में इच्छामृत्यु की अनुमति देने संबंधी उपरोक्त याचिका को मंजूरी दी। अदालत ने सम्मान के साथ मृत्यु के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा।
- अदालत ने दिल्ली चिकित्सा परिषद को हस्तक्षेप करने की अनुमति दी और नषिक्रयि अवस्था में इच्छामृत्यु पर दस्तावेज दायर करने का निर्देश दिया।
- वधिआयोग ने नषिक्रयि अवस्था में इच्छामृत्यु पर एक वधियक का मसौदा तैयार करने की सलाह दी और कहा कि उच्च न्यायालय में दायर ऐसी याचिकाओं पर वशिषज्जों की राय लेने के बाद ही फैसला हो।
- शीरष अदालत ने 2011 में अरुणा शानबाग के मामले में नषिक्रयि अवस्था में इच्छामृत्यु को मान्यता देते हुए अपने फैसले में ऐसे मरीज के जीवन-रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी थी जो एक सुवजिज नरिणय करने की स्थिति में नहीं हैं।
- केंद्र सरकार ने 15 जनवरी, 2016 को शीरष अदालत को सूचित किया था कि वधिआयोग ने अपनी 241वीं रिपोर्ट में चुनदा सुरक्षा उपायों के साथ नषिक्रयि अवस्था में इच्छामृत्यु की अनुमति देने की सफिरशि की थी।

(टीम दृष्टि इनपुट)

क्या है लविगि वलि?

- इच्छामृत्यु के लयि लखि गई वसीयत (लविगि वलि) एक ऐसा लखित दस्तावेज है, जसिमें कोई मरीज पहले से यह नरिदेश देता है कि मरणासन्न स्थिति में पहुँचने या रजामंदी नहीं दे पाने की स्थिति में होने पर उसे कसि तरह का इलाज दिया जाए, जबकि इच्छामृत्यु (पैसवि यूथनेशयि) वह स्थिति है जब कसि मरणासन्न व्यक्ति की मृत्यु सन्नकिट देखते हुए उसे इलाज देना बंद कर दिया जाता है।
- यह सुनशिचति करना अनविरय होगा कि 'लविगि वलि' की इजाजत केवल पैसवि यूथनेशयि के मामलों में ही दी जाए।
- लविगि वलि के माध्यम से ही कोई व्यक्ति यह बता सकेगा कि जब उसके ठीक होने की उम्मीद न हो तो उसे जबरन लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखना उचित है या नहीं?
- कोमा में पहुँच चुका मरीज स्वयं इस स्थिति में नहीं होता कि वह अपनी इच्छा व्यक्त कर सके। इसलयि उसे पहले ही यह लखिने का अधिकार होना चाहिये कि जब उसके ठीक होने की उम्मीद खत्म हो जाए तो उसके शरीर को यातना न दी जाए।

यहाँ एक बड़ा सवाल यह उठता है कि कोई यह कैसे तय कर सकता है कि उसके शरीर को बाद में यातना झेलनी पड़ेगी, इसलयि वह पहले ही लविगि वलि पर हस्ताक्षर कर दे?

- इस संबंध में एक उपाय यह हो सकता है कि डॉक्टरों की एक टीम द्वारा संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य की भली-भाँति जाँच की जाए, लेकिन कानूनी प्रावधानों के अभाव में ऐसा नहीं हो पाता।

संबंधित वधियक में क्या है?

केंद्र सरकार ने पैसवि यूथनेशयि को लेकर एक वधियक का मसौदा तैयार किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे 'द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट (प्रोटैक्शन ऑफ पेशेंट एंड मेडिकल प्रैक्टिसिन्स) बलि' नाम दिया है। इस मसौदा वधियक में लविगि पावर ऑफ अटॉरनी की इजाजत दी गई है। प्रस्तावित वधियक यह सुनशिचति करेगा कि असाध्य और भयंकर पीड़ा देने वाली बीमारी से पीड़ित मरीजों को इलाज से मना करने अर्थात जीवन रक्षक उपकरणों को हटाने की इजाजत है या नहीं। इस वधियक में चुनदा सुरक्षा उपायों के साथ नषिक्रयि अवस्था में इच्छामृत्यु की अनुमति देने की सफिरशि की गई है।

(टीम दृष्टि इनपुट)

एक्टवि और पैसवि यूथनेशयि में अंतर

'एक्टवि यूथनेशयि' और 'पैसवि यूथनेशयि' इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग 'इच्छामृत्यु' को इंगति करने हेतु किया जाता है।

एक्टवि यूथनेशयि: पहली वह स्थिति है, जब इच्छामृत्यु मांगने वाले कसि व्यक्ति को इस कृत्य में सहायता प्रदान की जाती है, जैसे- जहरीला इंजेक्शन लगाना या पेन कलिर का ओवरडोज देना।

उदाहरण: लगभग ढाई दशक पहले जब माकपा नेता बी.टी. रणदवि रक्त-कैंसर की असहनीय पीड़ा झेलते हुए मुंबई के अस्पताल में मृत्यु से संघरष कर रहे थे तब उन्होंने इच्छामृत्यु की मांग की थी। लेकिन इस वषिय में कोई कानून न होने की वजह से उनको यह अनुमति नहीं मिली। यदि उस समय कानून यह अनुमति देता तो यह सक्रयि इच्छामृत्यु होती क्योंकि असाध्य रोग से मुक्त और असहनीय कष्ट के नविरण के लयि मरीज की मांग पर चिकित्सक उन्हें मृत्यु की दवा देते।

(टीम दृष्टि इनपुट)

पैसवि यूथनेशयि: दूसरी वह स्थिति है जब इच्छामृत्यु के लयि कसि प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती। सरल शब्दों में कहें तो एक्टवि यूथनेशयि वह है, जसिमें मरीज की मृत्यु के लयि कुछ किया जाए, जबकि पैसवि यूथनेशयि वह है जहाँ मरीज की जान बचाने के लयि कुछ न किया जाए।

उदाहरण: बलात्कार की शिकार मुंबई की नर्स अरुणा शानबाग की इच्छामृत्यु को 2014 में अदालत से अनुमति तो नहीं मिली, लेकिन उनकी स्थिति रणदवि से अलग थी। अरुणा वर्षों से अचेत, जीवन-रक्षण प्रणालियों पर ही थी, उसे नहीं पता था कि वह जीवित है या नहीं, उसे कोई कष्ट है या नहीं। यदि उसे इच्छामृत्यु की अनुमति मिलती तो वह नषिक्रयि इच्छामृत्यु होती क्योंकि उसे किसी दवा की आवश्यकता नहीं थी, केवल जीवन-रक्षण प्रणाली हटाने की आवश्यकता थी। तब अदालत ने इसकी भी अनुमति नहीं दी थी। हालाँकि 2015 में उसे यह अधिकार मिल गया और उसे अपने कष्ट से तथा कष्ट देनेवाले संसार से मुक्ति मिल गई।

(टीम दृष्टि इनपुट)

इन दोनों के अलावा भी यूथनेशिया के कई स्वरूप हैं, जैसे-असिस्टेड सुसाइड, DNR (Do Not Resuscitate) अर्थात् पुनर्जीवित करने के प्रयास न करना, डॉक्टरनि ऑफ डबल इफेक्ट, फ्यूटाइल ट्रीटमेंट, इनडायरेक्ट यूथनेशिया, इनवोलंटरी यूथनेशिया।

इच्छामृत्यु के पक्ष में तर्क

संवधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार देता है, लेकिन इसकी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जीवन के अधिकार में गरमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। यदि कोई अशक्त और असहाय व्यक्ति जिसके जीवन में पीड़ा के अलावा और कुछ न हो और वह, जो अपने प्रत्येक कार्य के लिये दूसरों पर निर्भर रहता हो तो ऐसी स्थिति में उसके गरमा के साथ जीने के अधिकार का प्रत्यक्ष उल्लंघन होता है। इच्छामृत्यु के पक्ष में खड़े लोगों का तर्क है कि व्यक्ति के शरीर पर केवल उसका अधिकार है। यदि बीमारी के कारण व्यक्ति का दर्द सहनशक्ति की सीमा से ऊपर जा चुका है, तो उस व्यक्ति को इच्छामृत्यु के ज़रिये दर्द से मुक्ति पाने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिये।

लावते दंपती का मामला

सुप्रीम कोर्ट का यह जो फैसला आया है उसमें महाराष्ट्र के एक दंपति नारायण लावते (88) और इरावती लावते (78) भी एक पक्षकार थे। उनका कहना है कि अपने बुढ़ापे में वे समाज पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। नारायण लावते और उनकी पत्नी इरावती की कोई संतान नहीं है। इनके सगे भाई-बहन भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसे में दंपती को लगता है कि उनके जीने की अब कोई वज़ह नहीं बची है। अब शरीर भी उनका साथ नहीं देता है। इस उम्र में उनकी समाज के लिये कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। ऐसे में यदि कोई अन्याय उनकी देखभाल करने के लिये आगे आता है, तो वह संसाधनों की बर्बादी होगी। इसलिये उनको इच्छामृत्यु की इज़ाज़त मिलनी चाहिये, ताकि वे सम्मान और बर्बादी कहीं तकलीफ के इस संसार से वदिर्दि ले सकें।

यह दंपति भारत में इच्छामृत्यु के प्रतीक को 'सांस्कृतिक पछिड़ेपन' का एक लक्षण मानता है। उनका कहना है कि उनकी इच्छामृत्यु की मांग तर्क से प्रेरित है, न कि आध्यात्मिकता से। उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा है कि वे 'दया मौत' की अपनी याचिका पर अनुकूल प्रतिक्रिया चाहते हैं।

इसे पहले बहुचर्चित अरुणा शानबाग बनाम भारतीय संघ (2011) मामले में पहली बार इच्छामृत्यु का मुद्दा सार्वजनिक चर्चा में आया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्पिटल में 42 साल तक कोमा में रही नर्स अरुणा की इच्छामृत्यु की याचिका स्वीकारते हुए मेडिकल पैनल गठित करने का आदेश दिया था। हालाँकि, बाद में न्यायालय ने अपना फैसला बदल दिया था, लेकिन इस फैसले ने असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति को इच्छामृत्यु देने की बहस को आगे बढ़ाने का कार्य किया।

(टीम दृष्टि इनपुट)

इच्छामृत्यु के विपक्ष में तर्क

दुनिया के कुछ देशों (लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड और बेलजियम आदि) में इच्छामृत्यु की अनुमति है, लेकिन भारत इसके लिये अभी तैयार नहीं है। भारत की जटिल सामाजिक संरचना में यह एक बेहद जटिल मुद्दा है। इच्छामृत्यु की अनुमति देना या इसे वैध बनाना इसके दुरुपयोग की संभावनाओं को बल देगा। धन-संपत्तियां पारिवारिक दुश्मनी के कारण इच्छामृत्यु का दुरुपयोग टालना असंभव सा कार्य होगा और इसे मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन को समाप्त करने के एक तरीके के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इच्छामृत्यु का वरिध करने वालों का कहना है कि जीवन ईश्वर की देन है, इसलिये इसे वापस लेने का हक भी सिर्फ उसे है।

अन्य देशों में क्या है व्यवस्था?

संयुक्त राज् अमेरिका के कुछ राज्यों में इसकी मंजूरी है। ओरेगन, वाशिंगटन और मोंटाना में डॉक्टर की सलाह और उसकी मदद से मरने की इज़ाज़त है। स्विट्ज़रलैंड में इच्छामृत्यु तो गैर-कानूनी है, लेकिन व्यक्ति खुद को इंजेक्शन देकर जान दे सकता है। नीदरलैंड्स में मरीज़ की मर्जी के बाद डॉक्टर उसे इच्छामृत्यु दे सकता है। बेलजियम में सितंबर 2002 से इच्छामृत्यु वैधानिक हो चुकी है। ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस और इटली जैसे यूरोपीय देशों सहित दुनिया के अधिकांश देशों में इच्छामृत्यु की अनुमति नहीं है।

नषिक्रयि: 1970 के दशक के अंत में आई सुपरहिट फ़िल्म 'मुकद्दर का सकिंदर' में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पर फ़िल्माए गए एक उतने ही सुपरहिट गीत की शुरुआती पंक्तियाँ कुछ यूँ हैं... "रोते हुए आते हैं सब, हसता हुआ जो जाएगा..."। संवधान पीठ के एक न्यायाधीश ने इच्छामृत्यु पर अपना फैसला देते हुए अन्य तर्कों के अलावा इस गीत का भी हवाला दिया। उन्होंने राजकुमार सद्विधार्थ (भगवान बुद्ध) का हवाला भी दिया जो बीमार और मृत व्यक्ति को देखकर भयभीत हो गए थे।

अपने फैसले में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में यही तय करना था कि मरीज़ की पीड़ा को खत्म करने के लिये कानूनी तौर पर तुरंत मौत की इज़ाज़त दी जा सकती है या नहीं। उन्होंने एक प्राचीन ग्रीक दार्शनिक की कविता का हवाला दिया... "मृत्यु से क्यों डरू? जब मैं हूँ तो मृत्यु नहीं। उस चीज़ से मैं क्यों डरू जिसका अस्तित्व केवल तभी होता है जब मैं नहीं होता?..."

देश की सबसे बड़ी अदालत ने जीवन की तुलना 'दिव्य ज्योति' से करते हुए इसके सम्मान की बात की और मृत्यु को जीने की प्रक्रिया का हिस्सा बताया।

स्वाभिमिन के साथ जीना हमारे जीवन जीने के अधिकार का अभिन्न अंग है और जीवन एवं मृत्यु को अलग नहीं किया जा सकता । हर कषण हमारे शरीर में बदलाव होता है और बदलाव प्रकृति का नियम है । जीवन को मौत से अलग नहीं किया जा सकता और मृत्यु जीने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है ।

इच्छामृत्यु के अनुमति देने के संबंध में किसी प्रक्रिया का उल्लेख न तो संविधान में किया गया है और न ही संसद द्वारा बाद में जोड़ा गया है । इच्छामृत्यु की मांग करने वाले व्यक्ति को प्रायः न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है और प्रावधानों के अभाव में तथ्यों को देखते हुए विकानुसार फैसले किये जाते हैं । शीर्ष अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद परिस्थितियाँ निश्चित रूप से बदलेंगी । अब यूथनेसिया के संबंध में एक व्यापक कानून बनाया जाना चाहिये जो इसे स्वीकारने या अस्वीकारने के संबंध में मज़बूत और वैध तर्क प्रस्तुत करता हो ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/passive-euthanasia>

